



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2017/कार्तिक 11, 1939

No. 285]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2017/KARTIKA 11, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2017

विषय : इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'अनकोटेड कॉपियर पेपर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच की शुरुआत

फा.सं. 6/32/2017-डीजीएडी.— मै. जेके पेपर लिमिटेड, जेके पेपर लिमिटेड, दि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि., तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड और बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें आगे 'याचिकाकर्ता' या 'आवेदक' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष संगत सूचना के साथ एक आवेदन (जिसे आगे याचिका भी कहा गया है) दायर किया है जिसमें इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से अनकोटेड पेपर (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी,

मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद अनुमत सीमाओं के साथ निम्नलिखित आकारों की आयताकार शीटों में अनकोटेड पेपर है (क) 210 x 297 मिमी. जिसे ए4 आकार के रूप में भी जाना जाता है, (ख) 297 x 420 मिमी. जिसे ए3 आकार के रूप में भी जाना जाता है, (ग) 215 x 345 मिमी. जिसे एफएस या कानूनी आकार के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद का व्यावहारिक अर्थ अनकोटेड कापियर पेपर है। विचाराधीन उत्पाद को सामान्यतया (परंतु अनन्य रूप से नहीं) फोटोकॉपी या कापी पेपर के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसलिए उसे 'कापी पेपर', 'कापियर पेपर', 'फोटोकापी पेपर', 'मल्टीपर्पस पेपर', अनकोटेड कापियर पेपर, ए4 आकार के पेपर, ए3 आकार के पेपर या एफएस आकार के पेपर के रूप में आम तौर पर जाना जाता है। यह तैयार शीटों के रूप में होता है, जिसका भार अलग-अलग जीएसएम में होता है। यह सफेद कागज या एक पंच्ड पेपर हो सकता है और सतह की अलग-अलग रूप वाला होता है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखे गए उत्पाद लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त रीलों या बड़े आकार की शीटों के रूप में प्रयुक्त (अर्थात् ऊपर विनिर्दिष्ट आकारों से इतर) प्रकार का अनकोटेड पेपर है।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 4802 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

5. आवेदकों ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पादों के बीच सामग्री में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे मापदंडों के अनुसार तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु माना है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

6. यह आवेदन जेके पेपर लिमिटेड, दि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि., तमिलनाडु न्यूजप्रींट एंड पेपर्स लिमिटेड और बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। देश में विचाराधीन उत्पाद के पांच अन्य ज्ञात उत्पादक हैं अर्थात्, शेषशायी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, ट्राइडेंट ग्रुप, इंटरनेशनल पेपर एपीपीएम लि., ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लि. और सेंचुरी पल्प एंड पेपर हैं।

7. आवेदकों का उत्पादन भारत में उत्पादित समान उत्पाद के भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, आवेदकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। अतः आवेदक नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं।

घ. संबद्ध देश

8. वर्तमान जांच में शामिल देश इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर हैं (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है)।

ड. सामान्य मूल्य

9. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की सौदा कीमत की सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। तथापि, आवेदक ऐसी सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे। अतः

आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर सभी संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

च. निर्यात कीमत

10. आवेदकों द्वारा संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का दावा डीजीसीआईएस से प्राप्त सौदा वार आयात आकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से भारत औसत आयात कीमत के रूप में किया गया है। निम्न निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े और पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

छ. पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत के साथ की गई है जो प्रत्येक संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में भारी पाटन मार्जिन दर्शाता है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

12. आवेदकों ने समग्र रूप से और उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की भारी मात्रा, कीमत कटौती और लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय, नकद प्रवाह पर परिणामी भारी प्रतिकूल प्रभाव तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों और बाजार हिस्से में कमी और लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के निम्न स्तर के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से हुए कथित पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

13. आवेदकों ने इन आधारों पर वास्तविक क्षति के खतरे का दावा भी किया है कि संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि की दर काफी अधिक है, संबद्ध उत्पादकों के पास भारी अतिरिक्त क्षमताएं हैं, कीमत कटौती काफी अधिक है और भारतीय बाजार आकर्षक है जिससे आयातों में और वृद्धि होने की संभावना है और उनसे घरेलू बाजार में ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहे हैं।

झ. जांच की शुरुआत

14. प्राधिकारी प्रथमदृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पर्याप्त साक्ष्य हैं इसलिए प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरुआत करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में जांच की शुरुआत करते हैं।

ञ. जांच की अवधि (पीओआई)

15. याचिकाकर्ताओं ने अप्रैल 2016 – मार्च 2017 के रूप में जांच अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि के रूप में अप्रैल 2016 से जून 2017 तक (15 महीनों) की है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2013 – मार्च, 2014, अप्रैल 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल 2015 – मार्च, 2016 और जांच अवधि की अवधि शामिल होंगी।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें और अपने विचारों से अवगत करा सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

dgad.india@gov.in

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट www.dgtr.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

ठ. समय-सीमा

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित; हित के स्वरूप सहित की सूचना दें और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के चालीस दिनों; 40 दिनों के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर और तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड प्रति और साफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों; 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित; हित के स्वरूप सहित की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ड. गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर " गोपनीय " या " अगोपनीय " अंकित होना चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ण. असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2017

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Uncoated Copier Paper” originating in or exported from Indonesia, Thailand and Singapore

F.No. 6/32/2017-DGAD:— M/s JK Paper Limited, JK Paper Limited, The West Coast Paper Mills Ltd., Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited Ltd and Ballarpur Industries Limited (hereinafter referred to as ‘petitioners’ or ‘applicants’) have filed an application (also referred to as petition) along with relevant information before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of ‘Uncoated Paper’ (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from Indonesia, Thailand and Singapore (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the dumping and ‘injury’ exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

A. Product under consideration

3. The product under consideration for the purpose of present investigation is “uncoated paper in rectangular sheet of following sizes, with permissible limits (a) 210mm x 297 mm also known as A4 size; (b) 297mmx 420mm also known as A3 size; (c) 215mm x 345mm also known as FS or legal size.” The product under consideration

practically implies “uncoated copier paper”. The product under consideration is generally (but not exclusively) used as a photocopy or copy paper and therefore is popularly known as “copy paper”, “copier paper”, “photocopy paper”, “multipurpose paper”, “uncoated copier paper”, “A4 Size Paper”, “A3 Size Paper” or “FS Size Paper”. It is in the form of finished sheets; weighing in different gsm. It can be a white paper or a punched paper and in different smoothness of the surface. Specifically excluded from the scope of the product under consideration are uncoated paper of a kind used for writing, printing or other graphic purposes in reels or in large sized sheet (i.e., other than sizes specified above) forms.

4. Product under consideration is classified under customs heading 4802. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

B. Like Article

5. The applicants have claimed that there is no known difference in product produced by the applicants and exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the domestic industry in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Domestic Industry & Standing

6. The application has been filed by JK Paper Limited, The West Coast Paper Mills Ltd., Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited Ltd and Ballarpur Industries Limited. There are five other known producers of the product under consideration in the country, namely, Seshasayee Paper and Boards Limited, Trident Group, International Paper APPM Ltd., Orient Paper & Industries Ltd., and Century Pulp and Paper.
7. The production by the applicants constitutes ‘a major proportion’ of Indian production of the like product produced in India. Further, the applicants have claimed that they have neither imported the subject goods, nor are they related to any importer or exporter of the subject goods. The applicants, therefore constitutes “domestic industry” within the meaning of Rule 2 (b) and thus satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. Subject Countries

8. The countries involved in the present investigation are Indonesia, Thailand and Singapore (hereinafter referred to as ‘Subject Countries’).

E. Normal value

9. The applicants have submitted that efforts were made to get information/evidence of transaction price of subject goods in the domestic market of subject countries. However, applicants were not able to get such information. The applicants have therefore constructed normal value for all subject countries on the basis of cost of production in India duly adjusted.

F. Export Price

10. The export price has been claimed by the applicants as the weighted average import price from the subject countries based on the transaction-wise import data procured from DGCI&S. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges to arrive at the net export price.

G. Dumping Margin

11. The comparison of normal values with the ex-factory export price has been carried out, which shows a significant dumping margin in respect of the subject goods exported by each of the subject countries.

H. Evidence of Injury and Causal Link

12. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production & consumption, price undercutting, and consequent significant adverse impact on profitability, return on capital employed, cash flow, and deterioration in production, capacity utilization, sales and market share of the domestic industry and low

level of profits, cash profits & return on investment. There is sufficient prima facie evidence of 'material injury' being suffered by the domestic industry caused by alleged dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

13. The applicants have also claimed threat of material injury on the grounds that rate of increase in imports from the subject countries is significantly high, the subject producers have huge surplus capacities, price undercutting is significant and the Indian market is attractive which is likely to further increase in imports and cause suppressing or depressing effects in the domestic market.

I. Initiation of investigation

14. The authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between alleged dumping and injury, to justify initiation of anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry. Accordingly, the authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

J. Period of investigation (POI)

15. The petitioners proposed period of investigation as April 2016-March 2017. However, the Authority has considered the period April 2016 – June 2017 (15 months) as the investigation period for the purpose of present investigations. The injury investigation period shall cover the periods April 2013- March 2014, April 2014-March 2015, April 2015-March 2016 and the period of investigation.

K. Submission of Information

16. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi -110001.
Dgad.india@gov.in

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the authority at www.dgtr.gov.in) within the time limit set out below.

L. Time limit

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation .

M. Submission of Information on Confidential/Non-Confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set

marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such Information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

O. Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority